SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to inform the hon. Member that in Punjab the total which was sanctioned for four-laning of the existing two-lane national Highway No. 1, from Sarhind to Jullundur, was 96 kilometres which was sanctioned at a cost of Rs. 67.58 crores. Till today, we have spent about Rs. 43.53 crores. The target date to finish this road is December, 1992. No doubt there have been delays but the delays are due to unsatisfactory performance of the National Buildings Construction Corporation and also the Indian Railway Construction Corporation in respect of mobilisation of manpower and machinery. The Government of India have already taken some steps. They have expelled NBCC from the project package and the work has been awarded to M/s Gannon, another contractor. In the second package, the NBCC is carrying on the construction package. As per the target of the Ministry, by December, 1992 we expect to complete the work.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मूर्थल से अम्बाला की जो फोर लेनिंग है इसमें इंटर कांटिनेंटल फर्म शामिल थी, जिसमें एक फर्म बैंक आउट हो गयी.... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : वह कहते हैं कि वह इसमें नहीं आया।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : वर्ल्ड बैंक लोन का है। मूर्थल से अम्बाला की ओर लेनिंग की वर्ल्ड बैंक की स्कीम है। उसमें एक फारेन फर्म बैंक आउट कर गयी थी और इंटर कांटिनेंटल वालों ने कहा था कि हम इसको—

We will construct it on the same terms and conditions. What is happening to that?

SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to inform the hon. Member that as soon as this was brought to my notice, I wrote to the Chief Minister of Haryana about a month back. I am glad to say that the contract has been signed and I think the work should be in progress.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: We have been taking loan from the World Bank. If we look at the condition of the roads and the way they are built, may I ask the hon. Minister whether he is going to consider introducing the clause of quality control in all the agreements?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, quality control is already there. But we will see that...

MR. CHAIRMAN: They are of that quality.

SHRI JAGDISH TYTLER: Yes.

MR. CHAIRMAN: Question No. 222.

"लिट्टे" से निपटने के लिए श्रीलंका को सहायता

*222. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने "लिट्टे" की गतिविधियों से निपटने के लिए भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) सरकार को लिट्टे की गतिविधियों से निपटने में सहायता करने के लिए श्रीलंका सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी,

"ए मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भरलो पानी,

जो शहीद हुये हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।"

इतिहास के पन्नों पर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के बलिदान और खून की रंगत अभी गयी नहीं है और श्रीलंका सरकार ने लिट्टे की गतिविधियों से निबटने के लिये भारत सरकार से कोई सहायता, हो सकता है वर्तमान सरकार से न मांगी हो और

Question does not arise

कर दिया मिनिस्टर साहब ने। लेकिन सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सदन के नेता माननीय गृह मंत्री जी ने राजीव गांधी की हत्या के पीछे सुपर पावर्स की बात की थी, उस पर डी०एम०के० के नेता श्री मुरासोली मारन ने इसी सदन में कहा था कि अगर उसमें प्रभाकरन सम्मिलित है, लिट्टे का हाथ है राजीव गांधी की हत्या के लिये तो उन्हें बुलाया जाये और उनका ट्रायल किया जाये। यह डी०एम०के० के लीडर ने इस सदन में जो कुछ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था एस०आई०टी० के संदर्भ में, उस पर कहा था। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि एक बार हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स राजीव जी के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के आग्रह पर तमिलियंस और सिंहलियों के बीच में आत्मीयता और शांति स्थापित करने के लिये भेजी थी और वहां उसके लिये बन्दूक का बट उलट करके राजीव जी पर प्रहार किया गया था, यह सब इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है और अंत में उनकी हत्या हुई और स्थिति यह है कि एक ओर हत्यारे पोटेशियम सायनाइड खा करके, जहर खाकर के सोये जा रहे हैं और हमारी सरकार देखती रह रही है, कोई इंवेस्टीगेशन नहीं हो रहा है। हमको खुशी इस बात की है कि हमारे गृह मंत्री जी ने दूसरी जांच समिति जो कार्तिकेयन जी कर रहे थे उसके अलावा भी जिसमें सुपर पावर्स इंवोल्व्ड हैं उसके लिये बनायी जिससे सही इक्वायरी हो सके, उसके लिये मैं बधाई देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने श्रीलंका को लिट्टे की आतंकवादी कार्यवाहियों से निपटने के लिए और लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को पकड़कर भारत को सौंपने के लिए अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है? यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? यदि भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो क्यों भारत सरकार भारतीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन, जो राजीव गांधी हत्याकांड की एक प्रमुख कड़ी है और जिसने डंके की चोट पर स्वीकार किया था कि मैंने राजीव गांधी की हत्या कराई है, उसे भारत लाने या किसी अन्य स्थान पर उसका ट्रायल करने का विचार कर रही है? इसकी पूरी जानकारी सदन चाहता है मंत्री महोदय से।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, as I could understand his question on the dastardly assassination of late Prime Minister and Congress President, Shri Rajiv Gandhi, as the House knows, investigations are in progress. I can only say that whatever information Sri Lankan Government had provided to us, proved to be very useful. That is one aspect. On the second aspect of steps to expatriate Prabhakaran, it will again depend on what evidence of specific nature comes out against Prabhakaran in the course of investigations. I would not be able to comment on this matter. Home Ministry will be dealing with it when the question of expatriation arises, and they will approach us in this regard.

MR. CHAIRMAN: You can also approach the Sri Lankan Government for whatever help they need.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, सरकार एक है, गृह मंत्रालय हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, सबका दायित्व है इस काम में और प्रभाकरन डंके की चोट पर कह रहा है कि मैंने हत्या कराई है राजीव गांधी की और उसके बाद हमारी सरकार गोपनीयता का परदा डाल करके ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है

जिससे देश की 85 करोड़ जनता को संतोष हो । राज्यसभा के नेता और गृह मंत्री तथा भारत सरकार के प्रमुख व्यक्तित्व माननीय चव्हाण साहब ने सुपर पावर्स की बात की कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे सुपर पावर्स का हाथ है और हम लोगों ने मांग की कि उसकी जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए । अगर कोई सुपर पावर है इसके पीछे तो उस पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है और मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी हत्याकांड के पश्चात् हत्या की जांच कर रही एस० आई० टी० और दूसरी गुप्त एजेंसियां कितनी बार श्रीलंका के दौरे पर गई और इस दौरान क्या श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से लिट्टे उग्रवादियों की भारत में समुद्री रास्ते से घुसपैठ रोकने के लिए कोई आग्रह किया है ? वहां स्थिति यह थी कि किसी को जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और वह जो शनमुगम था, शहीद की तरह उसका दाह-संस्कार किया गया और शोक प्रकट किया गया और सारे बाजार बंद रहे । इस बारे में कोई भारत सरकार की तरफ से इन्वैस्टिगेट करने को तैयार नहीं है ।

तो श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से लिट्टे उग्रवादियों की समुद्री रास्ते से घुसपैठ रोकने के लिए क्या कोई आग्रह किया है और यदि किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ? एक और सीरियस मामला है कि पोटेशियम साइनाइड खाकर एविडेंस समाप्त करने के लिए लोग मर रहे हैं । मानव बम का प्रयोग आज तक नहीं हुआ था लेकिन राजीव गांधी को मारने के लिए जान पर खेलकर इसका प्रयोग किया गया । जिस प्रकार से ये लोग पोटेशियम साइनाइड खाकर एविडेंस नष्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके पीछे सुपर पावर्स का हाथ है । इस बारे में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने और होम मिनिस्ट्री ने कुछ किया है या ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और राजीव गांधी की हत्या रहस्यमय जाल में फंसकर रह जाएगी और हमेशा के लिए कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दी जाएगी ।

श्री सभापति : मंत्री जी विदेश मंत्रालय से संबंधित बात का ही जवाब देंगे । वैसे तो गवर्नमेंट एक ही है । चव्हाण साहब भी यहां बैठे हैं लेकिन क्वेश्चन आँवर का यह तरीका है कि जिस मंत्रालय में संबंधित सवाल पूछा जाए, उसी के बारे में वह मंत्री जवाब देते हैं । वे केवल विदेश मंत्रालय से ही संबंधित बातें बताएंगे ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस० आई० टी० और दूसरी एजेंसियां राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के सिलसिले में कितनी बार श्रीलंका गई हैं और क्या श्रीलंका सरकार ने हमारी सरकार से भारत में लिट्टे उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए कोई आग्रह किया है ?

श्री सभापति : उसका जवाब दे दिया न भाई । उसका जवाब दे दिया उन्होंने ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: When the Sri Lankan Foreign Minister was here last—and that was quite recently—Sri Lankans made very broad suggestions of co-operation in dealing with and putting down the threat of LTTE. These were only broad suggestions and there was no concrete proposal; no concreate proposal was really followed up after these broad suggestions on the visit of Sri Lankan Foreign Minister. When such concreate proposals are made, then we **shall look at the practicability** of these proposals and decide accordingly. Now, I can only say that this matter is being dealt with by the Home Ministry. Of course, as far this Ministry is concerned, LTTE is undoubtedly a **law and order threat and** a great threat in our own country and the dastardly assassination of Shri Rajiv Gandhi was an extreme example of how great a threat it is. At the same time, we are confident that we can deal with the situation within our country effectively and we would take concrete steps.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : प्रभाकरन को गिरफ्तार करके ट्रायल करने के लिए इस देश में आप कब तक ला रहे हैं, यह देश जानना चाहता है आपसे ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: I have already mentioned that for Prabhakaran to be extradited, there must be a case for extradition and the merits of the case are basically the concern of the Home Ministry. Whenever it comes to us, we will deal with it.

DR. RATNAKAR PANDEY: You are jointly responsible for it. You should have consulted the Home Minister and then come here.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, the IPKF was sent to Sri Lanka as per the agreement between Shri Rajiv Gandhi and the then Sri Lankan President. Now, Mr. Premadasa is facing an impeachment motion in the Sri Lankan Parliament. The Members who are moving the impeachment motion have made certain allegations against Mr. Premadasa. One of the charges is that Mr. Premadasa, while he was the President, had secretly supplied arms to the LTTE to fight the IPKF. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any information on it, whether the Sri Lankan Government supplied arms to the LTTE to fight the IPKF and, if so, what are they going to do.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Whatever happens in the Sri Lankan Parliament and the charges made therein are the internal affairs of Sri Lanka. As far as the question of the hon. Member is concerned, I don't have any information with me, at this point of time.

MR. CHAIRMAN: It concerns the LTTE and the arming of the LTTE by the Government of Sri Lanka is something of concern to the Government of India and the External Affairs Ministry must definitely come out with the information.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I do have any information, at the moment, on this.

MR. CHAIRMAN: Are you going to find out?

SHRI DIPEN GHOSH: You assure the House that you would collect the information and supply it to the House.

MR. CHAIRMAN: This news has come out in the electronic media that those who are asking for impeachment have made these allegations. Would you like to enquire into it and get at the rest of the whole things.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I take the suggestions.

SHRI YASHWANT SINHA: This has been publicised and they are not even aware of it. What is the Minister trying to say? Is he aware of it or is the Government of India not aware?

श्री सभापति : ठीक है, मैंने कह दिया ।

SHRI KAMAL MORARKA: The Chairman has made them aware.

SHRI DIPEN GHOSH: They don't have that much of input.

MR. CHAIRMAN: The opposition should provide that input because it is the responsibility of the whole House.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, आज जब यह गंभीर प्रश्न आया है हमारे सामने जिसे रत्नाकर जी ने बहुत विस्तार से रखा है तो इस समय गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं ।

श्री सभापति : आप गृह मंत्री से सवाल कर सकते हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने कहा कि वे यहां उपस्थित हैं ।

श्री सभापति : उपस्थित हैं, ठीक है । वे तो हाउस के लीडर हैं, उनको तो रहना ही चाहिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में चुनाई के अंतिम दिनों में गृह मंत्री ने एक बयान दिया था

जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इसमें सुपर पावर्स का हाथ है ।

श्री सभापति : आप तो रत्नाकर जी की बात दोहरा रहे हैं ।

SHRI SUBRAMANIAM SWAMY: It is only an authenticated version of that.

श्री शंकर दयाल सिंह : नहीं, मैं दोहरा नहीं रहा हूं । मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर सुपर पावर का हाथ है, हम जानते हैं कि पहले संसार में दो सुपर पावर्स थीं लेकिन अभी जो दुनिया की स्थिति है उसमें एक ही सुपर पावर बची है । एक सुपर पावर की स्थिति इस समय प्रश्नवाचक है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जुलाई में जो गृह मंत्री ने यह बात कही, उसकी विदेश मंत्रालय ने अच्छी तरह से जांच कर ली है कि वह सुपर पावर कौन है जिसका इस हत्याकांड में हाथ है और यदि उन्होंने इसकी जांच कर ली है तो वे उसका नामोल्लेख करें । अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की है तो यह बताएं कि वे इस सदन को कब बताएंगे कि कौन सी सुपर पावर का हाथ राजीव गांधी की हत्या में था ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, as the House knows, a Commission has been appointed to look into all aspects of the assassination and it is not possible for us to prejudge as to what will be findings of the Commission.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति जी, अभी विदेश राज्य मंत्री जी ने यह बताया सदन को कि जब श्रीलंका के विदेश मंत्री आये थे तो उन्होंने कोई प्रोपोजल रखी कि श्रीलंका और भारत मिलकर एल टी टी ई की समस्या का निदान करें । मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आज श्रीलंका के लिए एल टी टी ई इतनी बड़ी समस्या है, वह वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी एक तरह से कार्नर करते चले जा रहे हैं लेकिन ठीक उसके विपरीत भारत के अंदर एल टी टी की गतिविधियां बढ़ रही हैं बल्कि मैं तो यह समझता था कि यह तमिलनाडु तक ही सीमित हैं, वे जो शरणार्थी रूप में आये हैं उनमें से बहुत से मिलिटेंट हैं और जिस हत्याकांड की चर्चा हुई उसमें भी एल टी टी ई का नाम बहुत बार आया; अब ये चीजें बढ़ते-बढ़ते कर्नाटक में चली गई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब उनका विस्तार-प्रसार, भारत में बढ़कर, भारत की अखंडता के लिए एक संकट बन रहा है तो जो प्रोपोजल श्रीलंका के विदेश मंत्री ने रखी तो क्या विदेश मंत्री उसको परस्यू करेंगे ? यह जो एक खतरा दोनों देशों के लिए है उसके लिए कोई संयुक्त नीति, स्ट्रेटेजी, ट्रेनिंग, एक्सचेंज आफ प्रोग्राम, एक्सचेंज आफ इन्फरमेशन करने का प्रयास करेंगे ? अगर करेंगे तो सदन को बताएं ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: As I have mentioned, when the Foreign Minister of Sri Lanka came here, he did not make any concretae proposals. But he broadly suggested that there should be co-ordination and co-operation between the two Governments in dealing with the menace of the LTTE. After his visit, we have not received any concrete proposals.

MR. CHAIRMAN: His question is, will you take the initiative because this is spreading and it is very vital?

श्री अश्विनी कुमार : आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, यह हमें बताइये ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: Our positions, our feeling, at this point of time is that we can ourselves deal with the problem quite effectively. In the case of the assassination of Shri Rajiv Gandhi, they volunteered some help and some information, which was well-received and which proved fruitful. At the moment, our position is that we can ourselves deal with the situation quite effectively.

श्री अश्विनी कुमार : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । क्या यह श्रीलंका सरकार से बातचीत करके उनका सहयोग लेंगे ?

श्री सभापति : इन्होंने कहा है जब आवश्यकता होगी तो बात करेंगे ।

श्री अश्विनी कुमार : यह कहें कि सहयोग नहीं चाहिए या यह उनका सहयोग लेना नहीं चाहते । इसको स्पष्ट बतायें सदन में ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, in view of the feelings of the hon. Member, we will pursue his suggestion.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I would like to know from the hon. Minister whether he is aware—this point was also raised in the House before—that there is a threat by the LTTE to attack the coastal villages of Tamil Nadu? Is the Minister aware that the LTTE has selected certain coastal village for attack? This is a very serious matter. I would like to know whether the hon. Minister is aware of it and, if so, whether he has taken it up with the Sri Lankan Government?

Part(b) of my question also concerns our relationship with the Sri Lankan Government. The fishermen of Tamil Nadu, off the coast of Rameswaram, go for fishing near the island of Katchchatheevu are being captured by the Sri Lankan Navy, their boats are being destroyed. Several fishermen have lost their lives and many of them are in hospitals in Tamil Nadu. This is a very serious problem. It is agitating the minds of the people of the State. It is part of the agreement which was entered into earlier between the Sri Lankan Government and the Indian Government under which the Indian fishermen have fishing rights off Katchchatheevu and the right to dry their nets on the islands. I would like to know from the hon. Minister whether he will take up this issue with the Sri Lankan Government? I want a categorical answer because the Government of India has remained silent on the plight of the Tamil Nadu fishermen off the coast of Rameswaram. Will the Minister take it up? If the Sri Lankan Government does not respond, if our fishermen are not able to go for fishing safely, according to the terms of the agreement, will the Government consider reviewing the agreement.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the hon. Member is right that though the Island of Katchatheevu lies within the Sri Lankan waters, as per the Indo-Sri Lankan Maritime Boundry Agreement, the fishermen on this side, in our own country from Rameshwaram and other parts of Tamil Nadu, have a right of access to the Island for drying their nets, for attending the St. Anthony festival which takes place once in a while. So, these rights are there though the ownership of the Island as per the Agreement belongs to Sri Lanka. It is true, as the hon. Member has said, sometimes our fishermen stray within the maritime waters of Sri Lanka. They do stray within their maritime waters and we have the confirmed reports that the Sri Lankan Government has dealt with them in a manner that the hon. Member has suggested. Sir, we have already taken up this matter with the Sri Lankan Government and urged them to deal with these strayed fishermen in the due process of law and in a humane manner. Having taken up this matter recently, we expect a positive and favourable response from the Government of Sri Lanka.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I would like to know, when the Sri Lankan Foreign Minister made certain proposals whether he brought to their notice that this entire problem was because of the genocidal policy being pursued by the Sri Lankan Government against Tamils in Sri Lanka. While we have to deal with the LTTE as terrorist organisation' which is clearly involved in the assassination of Shri Rajiv Gandhi, they should do what they had committed to do, namely, to give the just right to the Tamil people as quickly as possible.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, when the Foreign Minister of Sri

Lanka was here we reiterated our well-known position that we are (1) for the unity and integrity of this country and (2) that as the Member has said, the legitimate rights of the Tamils must be respected and safeguarded.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: If the legitimate rights are not being given, why should we not, as the Soviet Union is for belconisation, ask them to have Eelam in Sri Lanka? If the legitimate rights of Tamils are not being conceded to by the Sri Lankan Government, why should the Government of India be committed to a single Sri Lanka? Let there be Tamil Eelam? Why should they come in the way?

MR. CHAIRMAN: Question No. 223.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I do not think my question was so sharp that he should be speechless on it. He should make some remark.

MR. CHAIRMAN: He cannot say that he will be a party to the decision of another State.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The question is, if the legitimate rights of Tamils are not being conceded to, what is the Government of India going to do?

MR. CHAIRMAN: In diplomatic channel, in diplomatic language, they are pursuing it.

Question No. 223.

Losses Suffered by Hindustan Shipyard, Visakhapatnam

*223. SHRI DINESHBHAI TRIVEDI:

SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

..Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the actual operational loss incurred by Hindustan Shipyard, Visakhapatnam, during the last three years;

(b) what is the amount of loss on account of pricing policy of the Government in respect of Hindustan Shipyard, Visakhapatnam during the above period; and

(c) what remedial action is being taken by Government to prevent further losses in HSL with the details thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The operating losses (namely losses without taking into account interest and depreciation) suffered by Hindustan Shipyard Limited (Visakhapatnam during the last 3 years are given below:

Year	Operating loss (Rs. in crores)
1988-89	23.79
1989-90	28.94
1990-91 (Provisional)	17.77

A number of factors contribute to the losses of Hindustan Shipyard. The more important ones are:

(a) Low productivity;

(b) Huge cost-price gap due to pricing formula;

(c) Long time over-runs in completion of ships;

(d) Huge interest burden arising out of borrowings for meeting the cost-price gap etc.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shiv Pratap Mishra.